CBDT ने DTAA के तहत PPT के लिये नए दिशा-निर्देश जारी किये

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कर अपवंचन को रोकने के उद्देश्य से दोहरा कराधान अपवंचन समझौते (DTAA) के तहत मुख्य उद्देश्य परीक्षण (PPT) लागू करने के लिये नए दिशानिर्देश प्रस्तुत किये हैं।

- ये दिशानिर्देश भावी रूप से लागू होंगे, तथा ग्रैंडफादरिंग प्रावधानों के कारण साइप्रस, मॉरीशस **और** सिंगापुर के साथ संधियों के लिये विशिष्ट छूट दी गई है।

मुख्य उद्देश्य परीक्षण (PPT) क्या है?

- **मुख्य उद्देश्य परीक्षण:** PPT अंतर्राष्ट्रीय कर नियमों का हिस्सा है जिसका उद्देश्य **कर संधियों के दुरुपयोग को रोकना** है।
  - आधार क्षरण एवं लाभ स्थानांतरण (BEPS) ढाँचे के अंतर्गत, PPT यह जाँच करता है कि क्या कोई **व्यावसायिक व्यवस्था वास्तव में वाणिज्यिक है या मुख्य रूप से करों से बचने के लिये बनाई गई है।**
    - यदि प्राथमिक उद्देश्य **कर-बचत है, तो संधि लाभ से इनकार** किया जा सकता है।
- **नये दिशानिर्देश:**
  - **PPT की प्रयोज्यता: PPT प्रावधान भावी प्रभाव से लागू होंगे, अर्थात पिछले निवेश, विशेष रूप से 1 अप्रैल 2017 से पहले के निवेश, अप्रभावित रहेंगे तथा उन पर पूर्वव्यापी जाँच नहीं की जाएगी।**
  - ग्रैंडफादरिंग प्रावधान: सिंगापुर, मॉरीशस और साइप्रस के साथ संधियों को विशिष्ट द्विपक्षीय प्रतिबद्धताओं के कारण PPT से बाहर रखा गया है।
    - इन संधियों के अंतर्गत विशिष्ट तिथियों से पहले किये गए निवेश मूल संधि प्रावधानों के अनुरूप होंगे।
  - **वैश्विक मानकों का संदर्भ:** नए दिशानिर्देश कर अधिकारियों को PPT प्रावधानों को लागू करते समय **BEPS एक्शन प्लान 6** और UN मॉडल टैक्स कन्वेंशन सहित अंतर्राष्ट्रीय कर ढाँचे का संदर्भ लेने के लिये प्रोत्साहित करते हैं।

दोहरा कराधान अपवंचन समझौते (DTAA) क्या हैं?

- **परिचय:** DTAA दो देशों के बीच एक संधि है जो करदाताओं को **दोहरे कराधान से बचने** में मदद करती है।
  - उदाहरण के लिये, भारत में निवेश से लाभांश अर्जित करने वाले NRI को आम तौर पर भारत और अमेरिका दोनों में करों का सामना करना पड़ता है। हालाँकि, DTAA के साथ, उन्हें समझौते की शर्तों के आधार पर केवल एक देश में कर लगाया जाता है।
    - इससे **अनिवासी भारतीयों को दो देशों में अतिरिक्त करों से बचने** में मदद मिलती है तथा कर चोरी कम होती है।
  - DTAA के तहत विभिन्न प्रकार की आय को कवर किया जाता है जिसमें व्यावसायिक लाभ, लाभांश, ब्याज, रॉयल्टी और पूंजीगत लाभ शामिल हैं।
  - प्रत्येक समझौते में यह निर्दिष्ट किया जाता है कि कौन सा **देश किस निश्चित आय पर कर** लगा सकता है। आमतौर पर इस संदर्भ में ओरिजिन वाले देश को प्राथमिक अधिकार प्रदान किया जाता है जबकि रेजिडेंस देश को कम दर पर कर लगाने की अनुमति दी जाती है।
- **भारत और DTAA:** भारत ने ऑस्ट्रेलिया, फ्राँस, जर्मनी, जापान, मॉरीशस, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के साथ **94 DTAA पर हस्ताक्षर** किये हैं।

आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण (BEPS) फ्रेमवर्क

- BEPS पहल एक OECD पहल है, जिसे G20 द्वारा अनुमोदित किया गया है, इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर अधिक मानकीकृत कर नियम प्रदान करने के तरीकों की पहचान करना है।
- BEPS का तात्पर्य उन कर रणनीतियों से है, जो **समग्र कॉर्पोरेट कर भुगतान को कम करने** के लिये विभिन्न देशों में कर नियमों में अंतर का फायदा उठाती हैं।

- वर्ष 2016 में स्थापित **BEPS फ्रेमवर्क के तहत कर चोरी से निपटने के लिये 147** देशों (भारत सहित) को एकजुट किया जाता है। इस फ्रेमवर्क में दो प्रमुख स्तंभ शामिल हैं:
  - **स्तंभ एक:** उपभोक्ता संबंधी देशों में मुनाफे का पुनर्आबंटन।
  - **स्तंभ दो:** बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिये **15% का वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट टैक्स (GMCT)।**
- **BEPS एक्शन 6** ट्रीटी शॉपिंग से संबंधित है और इसके तहत BEPS इन्क्लूसिव फ्रेमवर्क मेंबर्स के लिये न्यूनतम मानक निर्धारित होते हैं।
  - इसके तहत संधि के दुरुपयोग को रोकने के लिये नियमों के साथ कर समझौते करने से पहले कर नीति पर विचार करने के लिये अधिकार क्षेत्रों को मार्गदर्शन मिलता है।

UN मॉडल टैक्स कन्वेंशन

- **इससे द्विपक्षीय कर संधियों के संदर्भ** में रूपरेखा मिलती है। इसका उद्देश्य विकासशील देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए **दोहरे कराधान** से बचना एवं **कर चोरी** को रोकना है।
- इसके तहत देशों के बीच कर लगाने के अधिकारों पर दिशा-निर्देश प्रदान करने के साथ आयकर संबंधी नियमों को मानकीकृत करना शामिल है, जिससे देशों को सीमा-पार कर संबंधी मुद्दों के समाधान में मदद मिलती है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

??????????

प्रश्न. अप्रवासी सत्त्वों द्वारा दी जा रही ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं पर भारत द्वारा 6% समकरण कर लगाए जाने के निर्णय के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? (2018)

1. यह आय कर अधिनियम के भाग के रूप में लागू किया गया है।
2. भारत में विज्ञापन सेवाएँ देने वाले अप्रवासी सत्त्व अपने गृह देश में "दोहरे कराधान से बचाव समझौते" के अंतर्गत टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकते हैं।

निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

उत्तर: (d)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/cbdt-issues-new-guidelines-for-ppt-under-dtaas